

हमारी महानतम विश्वालता कभी भी न
गिरने में नहीं अपितु हर बार गिरने पर फिर
उठने में निहित होती है -कंपन्यूशियस

शतिष्ठाली और नीति-निर्माण

कांग्रेस पार्टी की सबसे शक्तिशाली और नीति-निर्माण करने वाले निकाय कांग्रेस कार्यसमिति ने आगामी लोक सभा चुनाव के मद्देनजर दो बड़े और महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। दोनों ऐसे फैसले हैं, जिनके नवाजे राहुल गांधी और डूबती कांग्रेस का भावित तय करेंगे। पहला, राहुल 2019 के लोक सभा चुनाव में पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे; और दूसरा, कांग्रेस समान विचारावाले दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जिनमें से डेढ़ सौ सीटें अपने बूते जीतने का इरादा रखती है। कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, यह तय करने का अधिकार किसी भी पार्टी को है, लेकिन कौन किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा, यह तय करने का अधिकार किसी एक पार्टी का नहीं हो सकता है। इसलिए कांग्रेस के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था, और कार्यसमिति ने सहयोगी दलों को तय करने का अधिकार कांग्रेस अध्यक्ष को दिया है। कार्यसमिति में किसानों की शक्ति, बेरोजगारी और अर्थिक स्थिति पर विचार किया गया। अदिवासी और दलित और पिछडे तबकों के मुँहों पर भी चंचल हुई। कांग्रेस कार्यसमिति का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सकार ने जिन लोकतांत्रिक संस्थाओं को खंडित किया है, सत्ता में अपने पर उनका पुरानाहार करेगी। कांग्रेस को याद होगा कि आपातकाल के दौरान लोकतांत्रिक संस्थाओं के साथसंबंध ज्यादा खिलावाड़ उसी ने किया था। सच कहा जाए तो कांग्रेस का पुनरुद्धार होना चाहिए। क्या कांग्रेस अध्यक्ष राहुल अपना ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे बड़े राज्यों में जरूर हो चुके कांग्रेस संघर्ष को पुनर्जीवित कैसे किया जाए? कार्यसमिति ने यह घोषित करके विपक्षी एकता को कमज़ोर कर दिया कि महागठबंधन के नेता राहुल होंगे। कांग्रेस को समझना होगा कि अपने-अपने राज्यों में जो विषयक के नेता मजबूती के साथ स्थापित हैं, वे राहुल को अपना नेता क्यों स्वीकार करेंगे या कांग्रेस की सरपरस्ती में चुनाव लड़ेंगे? प. बंगला में ममता बनर्जी, ओडिशा में नवीन पटनायक, अंध्र में चंद्रबाबू नायडू और उत्तर प्रदेश में मायावती के पास राहुल की तुलना में राजनीतिक अनुभव ज्यादा है। इसलिए राहुल को प्रधानमंत्री बनाने के लिए कांग्रेस को कम से कम दो सौ सीटें जीती होंगी। कांग्रेस इस बात को जिती जल्दी समझ ले, उन्होंने तो उसके लिए बेहतर है।

केन्द्र से नया कानून

हत्या और हिंसा देश के हर विवेकशील व्यक्ति के लिए चिंता का कारण है। इसे रोकने के लिए जो कुछ भी करने की आवश्यकता है, वह केन्द्र एवं राज्य सरकार को करना ही चाहिए। चूंकि कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, इसलिए इसको रोकने तथा हिंसा व हत्या के अपाधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जिम्मेवारी उहाँ की है। बाबुजुद केन्द्र एकदम मुकदमकार नहीं रह सकता। केन्द्र सरकार की ओर से यह खबर आ रही है कि इसके लिए भारतीय दंड संहिता में अलग से प्रावधान बनाए जाएंगे। वास्तव में हर कुछ अंतराल पर ही रही भीड़ की हिंसा के बाद इसके लिए अलग से नए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सर्वोच्च न्यायालय की ओपनें आदेश में केंद्र से नया कानून बनाने का कारोबार हो आ रहा है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से केंद्र कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग राज्य ही नहीं अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। खाने के बारे कर्माई में समृद्धि नहीं आती है। महाराष्ट्र सरकार ने फरमान जारी किया कि केन्द्र की ओपनें एकान्तराली छाता एवं सीमोंसिंहों को उपलब्ध होगा। इसकी तात्पुरता की ओपनें आदेश में अलग से बर्बाद हिंसा के बाद इसके लिए अलग से नए कानून की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने आदेश में केंद्र से नया कानून बनाने का कारोबार कहा है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के बाद कानूनी कार्रवाई में एकरूपता आ जाएगी। इसके पहले गृहमंडी राजनाथ सिंह ने यह भी जानकारी दी कि केन्द्र की ओर से राज्यों को दो-दो बार एडवायरिंग भी जारी की जा चुकी है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसको भी जिम्मेवारी उहाँ की है। किंतु कोई यह समझे कि नए कानूनी तो यह सही नहीं होगा। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से भी कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। इसके कार्रवाई की ओपनें आदेश में केंद्र की ओर से नया कानून बनाने का कारोबार कहा जाता है। तो देखत हैं केन्द्र की ओर से एक कानून का प्रावधान आ रहा है। आगे भी इसी की हिंसा के लिए विशेष कानून हो जाए तो यह भी पुलिस प्रशासन के लिए अलग-अलग जिलों में भी एक समान धाराएं नहीं लगाई जातीं। नए कानून के ब

